

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी  
उत्तर प्रदेश।

विषय:- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के सतत संचालन के लिये उपयोग किये जा रहे डिजीशक्ति वेब पोर्टल में डाटा को वेरीफाई, अप्रूव एवं लॉक करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु पोर्टल को पुनः खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि शासनादेश संख्या 975/77-1-2022-156/2021 दिनांक 18 जुलाई, 2022 के अनुसार आगामी 05 वर्षों के लिये स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किया जाना निर्धारित किया गया है। वर्ष 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना लागू की गयी, जिसके क्रम में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की ओर से यूपीडेस्को नोडल संस्था के रूप में कार्यरत है।

अवगत कराना है कि योजना के सतत क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु पूर्व में विकसित किये गये डिजीशक्ति वेब पोर्टल में छात्र/छात्राओं का डाटा द्वितीय चरण की कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 03.08.2022 को कोर्स मास्टर अपलोड एवं लॉक करने हेतु तथा 19.09.2022 से 2021-22 के छात्र/छात्राओं के डाटा को एडिट, प्रमोट एवं 2022-23 के छात्र-छात्राओं के डाटा को अपलोड करने के लिये पुनः खोला गया था।

उक्त के क्रम में डिजीशक्ति पोर्टल को उक्त कार्यवाही हेतु दिनांक 19.10.2022 को बन्द करते हुये अपलोड/प्रमोट हो चुके डाटा को संस्थान स्तरीय लॉगिन द्वारा वेरीफाई, विश्वविद्यालय/बोर्ड/सोसाइटी/कांसिल स्तरीय लॉगिन द्वारा अप्रूव एवं विभाग स्तरीय लॉगिन द्वारा लॉक करने की कार्यवाही हेतु खोला गया था परन्तु पोर्टल पर डुप्लीकेट डाटा रन करने हेतु दिनांक 26.10.2022 को उक्त कार्यवाही हेतु बन्द करा गया था।

उपरोक्त विषयक अनुसार पोर्टल को संस्थान स्तरीय लॉगिन द्वारा वेरीफाई, विश्वविद्यालय स्तरीय लॉगिन द्वारा अप्रूव एवं विभाग स्तरीय लॉगिन द्वारा लॉक करने की कार्यवाही हेतु दिनांक 07.11.2022 से 12.11.2022 तक पुनः खोला जा रहा है।

कृपया उक्त से अवगत होते हुये अपने जनपद के अन्तर्गत आने वाले समस्त संस्थानों एवं विश्वविद्यालय/बोर्ड/सोसाइटी/कांसिल के इस योजना से सम्बन्धित नोडल अधिकारी को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार विनीत)  
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उ.प्र. शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन।

(कुमार विनीत)  
प्रबन्ध निदेशक